Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 91–2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 29, 2018 (JYAISTHA 8, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 मई 2018

संख्या 14/5/2017–3–क–II.— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16) की धारा 149 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013 दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन तुरन्त प्रभाव से करते हैं, अर्थात्–

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्तूबर 2013 में,–

1. पैरा 5 में, उप पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

   (ख) देर से अदायगी की दशा में, प्रतिमाह एक 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज या उसका भाग प्रभारित किया जाएगा – परन्तु वर्ष 2010–11 से 2016–17 तक के लिए सम्पति कर के बकाया पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि 30–06–2018 तक उनके बकाया भुगतान कर दिए जाते है।

2. जो सम्पति मालिक सम्पति कर का भुगतान कैशलैस तरीके से करवायेगा, उसे 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।

आनन्द एम० शरण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 29th May, 2018

No. 14/5/2017–3C–II.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.85/H.A.16/1994/ S.O.87/2013, dated the 11th October, 2013 with immediate effect, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) Notification No. S.O. /H.A. 16/ 1994/ S. 87/ 2013, dated the 11th October, 2013,–

1. In para 5, for sub-para (b), the following sub para shall be substituted, namely:-

(b) in case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged: Provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2017-18 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 30.06.2018.

2. 1% rebate shall be given to property owner who will pay the property tax by cashless system.

ANAND M. SHARAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

56313—C.S.—H.G.P., Chd.